संख्या-08/2022/।/151203/38-4-2022-02/2021

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-जी0ओ0-12/सम्प्रेक्षा/मु0मं0आ0यो0(अनु0-81)/2021-22, दिनांक-24 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष 2021-22 के निर्धारित 1601+559 कुल 2160 आवास लक्ष्यों के सापेक्ष 1601 लाभार्थियों की अवशेष तृतीय किश्त की धनराशि रूपये 160.10 लाख एवं अतिरिक्त चेरो अनुसूचित जनजाति के चयनित 559 लाभार्थियों के आवास निर्माण कराने हेतु प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि एवं द्वितीय तथा तृतीय किश्ति की धनराशि रू0 503.10 लाख समस्त कुल धनराशि रूपये 663.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक से योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 में अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: आपके उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 के निर्धारित 1601+559 कुल 2160 आवास लक्ष्यों के सापेक्ष 1601 लाभार्थियों की अवशेष तृतीय किश्त की धनराशि रूपये 160.10 लाख एवं अतिरिक्त चेरो अनुसूचित जनजाति के चयनित 559 लाभार्थियों के आवास निर्माण कराने हेतु प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि एवं द्वितीय तथा तृतीय किश्त की धनराशि रू0 503.10 लाख समस्त कुल धनराशि **रूपये 663.20 लाख (छ: करोड़ तिरसठ लाख बीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 से आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) पात्र लाभार्थियों की संख्या, आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्य आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/योजना के दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रतर किश्त/धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(7) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(8) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(9) योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि स्टेट नोडल बैंक एकाउन्ट से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अन्तरित की जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-6/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक-02.02.2018, शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध)/2017, दिनांक-04.02.2019, शासनादेश संख्या-17/2019/248/38-4-19-123(विविध)/2017 टी.सी-1, दिनांक-28.06.2019, शासनादेश संख्या-09/2021/150/38-4-21-123(विविध)/2017 टी.सी-1, दिनांक-18.03.2021, शासनादेश संख्या-19/2021/240/38-4-21-123(विविध)/2017 टीसी-1, दिनांक 25.06.2021 एवं शासनादेश संख्या-44/2021/671/38-4-2021-123(विविध)/2017, दिनांक 27.12.2021 में विहित प्राविधानों के अधीन योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण में व्यय की जायेगी।

(12) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 के अधीन लेखाशीर्षक ''4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-02-मुख्यमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)-24-वृहत् निर्माण कार्य'' नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-2-3463/दस-2021-22, दिनांक-28.03.2022 में प्राप्ति सहमति के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव।

संख्या-08/2022/।/151203, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(5) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्यक कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(10)बजट प्रकोष्ठ अनुभाग, समाज कल्याण विभाग।
(11)श्री लाल धीरेन्द्र राव, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।